



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 41]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 6, 2004/माघ 17, 1925

No. 41]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 6, 2004/MAGHA 17, 1925

पोत परिवहन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 फरवरी, 2004

का.आ. 170(अ).—दिनांक 7-5-2003 की असाधारण अधिसूचना सं. का. आ. 502(अ) के द्वारा पी.आर. सुब्रमण्यम् एवं अन्य बनाम संघ सरकार एवं अन्य (2002 की रिट याचिका सं. 099) के मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय के दिनांक 15 जनवरी, 2003 के आदेशानुसार श्री बी. एन. मахीजा की अध्यक्षता में गठित एक सदस्यीय न्यायाधिकरण तथा दिनांक 7 नवम्बर, 2003 की असाधारण अधिसूचना सं. का.आ. 1279(अ) जिसके द्वारा न्यायाधिकरण का कार्यकाल 6 नवम्बर, 2003 से 3 माह के लिए बढ़ाया गया था, के क्रम में केन्द्रीय सरकार न्यायाधिकरण के कार्यकाल को एतद्वारा 6-2-2004 से आगे तीन माह और बढ़ाती है। उल्लिखित अधिसूचना के साथ अनुबंधित सौंपे गए कृत्य तथा निबंधन एवं शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

[फा. सं. एस.आर.-11014/1/2003-एम.ए.]

आर.के. जैन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th February, 2004

S.O. 170(E).—In continuation of Extraordinary Gazette Notification No. S.O. 502 (E) dated 7-5-2003 constituting One Man Tribunal under the chairmanship of Shri B.N. Makhija in the matter of Shri P. R. Subramaniam and Others Versus Union of India and Others (Writ Petition No. 099 of 2002) in accordance with the Calcutta High Court Order Dated 15-1-2003 and S.O. 1279(E) dated 7th November, 2003 extending the term of the Tribunal by 3 months beyond 6th November, 2003, the Central Government grants further extension of time to the Tribunal for 3 months with effect from 7th February, 2004. The Terms of Reference and other terms and conditions annexed to the said notification will remain unchanged.

[F. No. SR-11014/1/2003-MA]

R. K. JAIN, Jt. Secy.